

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 24/23

GCMS NO 2023/49

लक्ष्मीनारायण पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

अपीलांत

बनाम

1. प्यारे लाल पुत्र कल्याण
2. मोत्या पत्नि स्व०कल्याण
3. लाडबाई पत्नि स्व०श्योराम
4. अंकेश पुत्र श्योराज नाबालिग
5. रिकू पुत्री श्योराज नाबालिग जरिये माता लाडबाई बेवा श्योराज मीना
6. फोरी पत्नि प्यारेलाल जाति मीना निवासी सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

रेसपो०

(अपील विरुद्ध मु०नं० 22/20 निर्णय दिनांक 21.12.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा)

अभिभाषक अपीला० श्री संदीप शर्मा

अभिभाषक रेसपो० श्री अजय शेखर दवे

दिनांक 04.11.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला० की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 21.12.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांत/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी ख०न० 1081 रकबा 0.3000, ख०न० 1094 रकबा 0.2000, ख०न० 2812/4259 रकबा 0.0700 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5700 वके ग्राम सारसोप प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। बाहमी बंटवारे के आधार पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 ने उक्त भूमि का आपस मे बंटवारा कर लिया है। बंटवारा अनुसार प्रार्थी के हिस्से की आराजी ख०न० 1081 की संपूर्ण रकबा प्रार्थी के कब्जे काश्त मे अर्स दराज से चला आ रहा है। खाता संख्या 1035 की शेष आराजी ख०न० 1094,2512/4259 हमेशा से अप्रार्थीगण/रेसपो० के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। प्रार्थी जन्मांध है कुछ दिखाई नही देता है। प्रार्थी हमेशा से




राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

कब्जे काश्त की आराजीयात ख0न0 1081 को काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की कब्जे काश्त की आराजीयात ख0न0 1081 पर नाजायज रूप से कब्जा करना चाहते हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ गाली गलौच व मारपीट करते हैं। अप्रार्थी प्यारे लाल पत्नि को आगे करके प्रार्थी के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। अप्रार्थी उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की आराजीयात पर कब्जा करने पर आमादा भूखे मरने की नोबत आ जावेगी। खाता संख्या ग्राम सारसोप की भूमि ख0न0 1081,1094, 2812/4259 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.5700 का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त भूमि मौके पर कब्जे अनुसार विधिवत बंटवारा किया जाकर प्रार्थी को ख0न0 1081 का खातेदार घोषित किया जाकर प्रार्थी की सेपरेट खातेदारी दर्ज की जावे एवं शेष भूमि ख0न0 1094,2812/4259 को अप्रार्थीगण 1 ता 5 के सेपरेट खातेदारी में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन किया जावे। जिसका प्रार्थी को अधिकार है। भूमि ख0न0 1081 में अप्रार्थी को मजाहमत नहीं करने हेतु पाबन्द फरमाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्प0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से खारिज योग्य है। जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 1035 में अपीलांट की आराजी ख0न0 1081 ,2812/4259 वाके ग्राम सारसोप 1/2 भूमि का खातेदार काश्तकार है। बांहमी बंटवारे के अनुसार ख0न0 1081 प्रार्थी/अपीलांट के कब्जे काश्त में आई शेष ख0न0 1094 व 2812/4259 रेस्प0 के हिस्से व कब्जे में चली आ रही है। अपीलांट जन्मांध है आंखों से कुछ नहीं दिखता है इस कारण रेस्प0 , अपीलांट की कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजीयात को काश्त करने में मजाहमत करते हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात पर विश्वास नहीं करके कानूनी भूल की है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अपीलांट अंधा होने के कारण कमाकर खाने में असमर्थ है जीवन यापन का कोई जरिया नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा रेस्प0 को पाबन्द फरमाया जावे कि अपीलांट/प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजीयात ख0न0 1081 वाके ग्राम सारसोप के काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे ना ही अन्य से करावे।

रेस्प0 के अधिवक्ता ने बहस में अवगत कराया कि अपीलाधीन निर्णय विधि अनुरूप होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में बंटवारे का वाद विचारधीन होने से अपीलांट/प्रार्थी के हिस्से में आराजी ख0न0 1081 की खातेदारी प्रार्थी/अपीलांट के नाम किस



राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्रकार आ सकती है। अपीलांत/प्रार्थी एवं रेस्पोंड/अप्रार्थी विवादित भूमि के सहखातेदार है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सहखातेदार को विधि अनुरूप पाबन्द नहीं किया गया है। जो विधि के सिद्धान्त के अनुरूप है। रेस्पोंड द्वारा अपीलांत को किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गई यदि किसी प्रकार की कोई धमकी रेस्पोंड द्वारा अपीलांत/प्रार्थी को दी जाती तो उनके द्वारा पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। अपीलांत द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य गलत रूप से पेश किये गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत बंटवारे के बिना एक खातेदार का कब्जा मानकर अन्य सहखातेदारों को पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं मानकर ही निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांत की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि भूमि ख०न० 1081 रकबा 0.3000, ख०न० 1094 रकबा 0.2000 एवं ख०न० 2812/4259 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.5700 है। वाके ग्राम सारसोप प्रार्थी एवं प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जिसमें प्रत्येक का 1/2, 1/2 किये जाने का वाद अधिनस्थ न्यायालय में विचारधीन होना उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। अपीलांत द्वारा कब्जे के आधार पर केवल मात्र ख०न० 1081 रकबा 0.3000 पर रेस्पोंड को पाबन्द करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारे का वाद अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण ही केवल कब्जे के आधार पर किसी सहखातेदार को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं मानकर ही निर्णय पारित किया है। जो विधि के अनुरूप है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलांत खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांत खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के प्रकरण संख्या 22/20 में पारित निर्णय दिनांक 21.12.22 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(लक्ष्मी प्रियंका प्रबलित्त)
राजस्व विभाग प्रमुख प्राधिकारी